## दिल्ली को दहलाने की फिराक में लश्कर-ए-तैयबा: आईईडी हमले की साजिश


# अशोका एक्सप्रेस

ASHOKA
SMA - Ashoka Express Publication

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

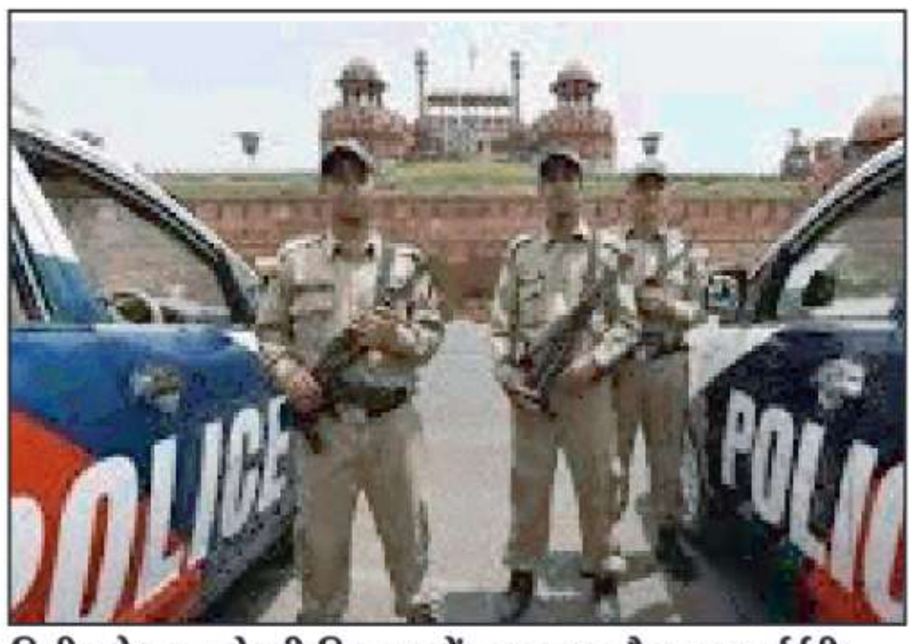

● वर्ष: 29 ● अंक : 07 ● नई दिल्ली ● 23 से 28 फरवरी 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये


# प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने फिर आत्मसमर्पण करेंगे - कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यापार समझौते पर अमेरिका से दोबारा बातचीत नहीं कर सकते और वह फिर से समर्पण कर देंगे। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक शुल्क को खारिज कर दिया, जिससे ट्रंप के आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है। न्यायाधीशों ने बहुमत के फैसले में कहा कि संविधान बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिकी कांग्रेस (संसद) को कर लगाने की शक्ति देता है, जिसमें शुल्क भी शामिल है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं। उनका विश्वासघात अब उजागर हो गया है। वह (व्यापार समझौते पर) दोबारा बातचीत नहीं कर सकते। वह फिर से समर्पण कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, बिना सिर-पैर वाली विदेश नीति या एकतरफा समर्पण? जिस ट्रैप डील ने भारत से भारी रियायतें लीं, मोदी सरकार ने उसमें फंसने से पहले शुल्क पर अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, संयुक्त वक्तव्य में भारत को होने वाले कई अमेरिकी निर्यातों पर शून्य शुल्क की बात कही गई है जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र का द्वार अमेरिकी वस्तुओं के लिए खुल जाएगा। साथ ही, 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान आयात करने की



योजना, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता और डिजिटल मोर्चे पर कई कर रियायतों की बात संयुक्त वक्तव्य में कही गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने के लिए उन पर किसने दबाव डाला? क्या यह एप्स्टीन फाइलें थीं? उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत सरकार अपनी गहरी नींद से जागेगी और एक निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के आत्मसम्मान और हमारे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगा? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि यह समझौता एक कठिन परीक्षा की तरह बन गया है जिसका सामना देश को प्रधानमंत्री के आत्मसर्मपण के कारण करना पड़ रहा है। रमेश ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए यह सवाल भी किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि दो फरवरी 2026 की रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा करें? अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ट्रंप ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का अमेरिका और भारत द्वारा इस महीने की शुरुआत में घोषित व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपने अछे संबंधों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, कोई बदलाव नहीं होगा। वे (भारत) शुल्क का भुगतान करेंगे और हम शुल्क नहीं देंगे। इसलिए भारत के साथ समझौता यही है कि वह शुल्क देगा यह पहले की स्थिति से उलट है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी सजन व्यक्ति हैं, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में वह जिनके समकक्ष थे उनसे कहीं अधिक होशियार थे। वह हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए हमने भारत के साथ एक समझौता किया। अब यह एक निष्पक्ष समझौता है और हम उन्हें शुल्क नहीं दे रहे हैं.

### रीजीजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना

## एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन भारत के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी युवा शाखा के कार्यकर्ताओं को लगाकर देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है। रीजीजू ने विरोध प्रदर्शन को शर्मनाक बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस युवा शाखा का विरोध प्रदर्शन कोई गलती नहीं, बल्कि भारत पर हमला करने के लिए पार्टी द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश थी। उन्होंने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी युवा शाखा का इस्तेमाल करके देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस द्वारा युवाओं का इस्तेमाल देश को बदनाम करने के लिए करना, इससे अधिक शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। रीजीजू ने कहा कि जहां पूरा देश शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के कृत्यों की निंदा कर रहा है, वहीं पार्टी और उसके नेता माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, जब भारत प्रगति करता है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भारत को बदनाम करने के लिए चौबीसों घंटे साजिशें रचते रहते हैं। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप राष्ट्रविरोधी कृत्यों में लिप्त होना कब बंद करेंगे?

# अमेरिकी टैरिफ डील, राहुल बोले- मोदी ने विश्वासघात किया

## खड़गे का आरोप- सरकार ट्रम्प की ट्रैप डील में फंसी, भारत से भारी रियायतें छीन लीं

नई दिल्ली ।

अमेरिकी टैरिफ डील पर विपक्ष फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीएम मोदी पर समझौता करने का आरोप लगाया। कहा कि उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि पीएम इस व्यापार समझौते में फिर से आत्मसमर्पण कर देंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना मोदी सरकार ने इतनी जल्दबाजी में एक ट्रैप डील में शामिल क्यों हुए, जिसने भारत से भारी रियायतें छीन लीं। बता दें अमेरिका ने 2 फरवरी को भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18फीसदी किया था। वाणिय मंत्री पीयूष गोयल ने 20 फरवरी को बताया कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा।

**खड़गे ने कहा- मोदीजी को सचाई बतानी चाहिए**

**1. मल्लिकार्जुन खड़गे-** मोदी जी को देशवासियों के सामने खड़े होकर सचाई बतानी चाहिए। किसने या किन कारणों ने आपको भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने के लिए दबाव डाला? क्या यह एप्सटीन फाइल्स थीं। क्या भारत सरकार अपनी गहरी निष्क्रियता से जागेगी? क्या 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान, साथ ही किसानों, मजदूरों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाला एक निष्पक्ष व्यापार समझौता पेश करेगी।

**2 . जयराम रमेश-** यदि सरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए 18 दिन और इंतजार करती, तो भारतीय किसानों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सकती थी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता वास्तव में एक परीक्षा है, जिसे प्रधानमंत्री की हताशा और आत्मसमर्पण के कारण भारत पर थोपा जा रहा है।

**3. मनीष तिवारी-** यह फैसला दुनिया की अदालतों के लिए संदेश है कि उन्हें कार्यपालिका की यादती रोकनी चाहिए।
अगर न्यायपालिका अपना काम नहीं करेगी तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल सकता है। इस फैसले से ट्रम्प प्रशासन, न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।

**4. प्रियंका चतुर्वेदी-** भारत ने इस समझौते में जल्दबाजी क्यों की? भारत को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। अभी भारतीय निर्यात पर 10 फीसदी टैरिफ है, जबकि अमेरिकी आयात पर लगभग जीरो टैरिफ, इससे डील असंतुलित दिखती है।

# अजित पवार के भतीजे का आरोप- प्लेन क्रैश बड़ी साजिश

मुंबई । महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत का मामला अब सियासी तूफान बन गया है। एनसीपी-एसपी के विधायक रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू को पद से हटाने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। रोहित पवार ने कहा कि यह हादसा साधारण दुर्घटना नहीं हो सकता और इसकी गहराई से जांच जरूरी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र की प्रति भेजी है। रोहित पवार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 28 जनवरी की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। इस हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि मामला राजनीतिक साजिश है या व्यावसायिक साजिश। उनके अनुसार, जिस एयर चार्टर कंपनी वीएसआर का विमान था, उसके खिलाफ कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

**वीएसआर कंपनी और कथित लिंक पर सवाल**

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि वीएसआर कंपनी और कुछ प्रभावशाली लोगों के बीच संबंधों की



जांच होनी चाहिए। उन्होंने पत्र में लिखा कि कंपनी और नागरिक उड्डयन मंत्री की पार्टी के बीच संभावित लिंक की स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो। उनका कहना है कि उद्योग और राजनीति के कुछ ताकतवर लोग

**दुर्घटना के समय कई धमाके हुए थे, विमान में पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे रोहित पवार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, उड्डयन मंत्री को हटाने की मांग की**

इस कंपनी के पीछे हैं, जिससे जांच पारदर्शी नहीं हो पा रही है। उन्होंने डीजीसीए की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की।

**ब्लैक बॉक्स और विस्फोट पर संदेह**

रोहित पवार ने हादसे के ब्लैक बॉक्स को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय एक नहीं, कई धमाके हुए थे। उनके मुताबिक, विमान में सामान रखने वाले हिस्से में अतिरिक्त पेट्रोल के कैन रखे गए थे, जिससे आग भड़की। उन्होंने कहा कि इन सभी पहलुओं की तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से जांच होनी चाहिए।

**मंत्री के इस्तीफे की मांग**

पत्र में रोहित पवार ने प्रधानमंत्री से अपील की कि अगर निष्पक्ष जांच करनी है तो पहले नागरिक उड्डयन मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने देश और महाराष्ट्र के लिए योगदान दिया है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनका दावा है कि जब तक शक्तिशाली लोगों की भूमिका की जांच नहीं होगी, तब तक सचाई सामने नहीं आएगी। इस हादसे को लेकर एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस पहले ही सवाल उठा चुके हैं और फाउल प्ले की आशंका जता चुके हैं। अब रोहित पवार के सीधे प्रधानमंत्री से दखल की मांग करने से मामला और गरमा गया है। आने वाले दिनों में इस पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्रतिक्रिया अहम होगी। फिलहाल यह मामला सियासत और जांच दोनों के केंद्र में है।

# तकनीक के जरिए मातृभाषाओं को बचाने की जरूरत

उमेश चतुर्वेदी ।

**तकनीकी** दौर में मातृभाषाएं सबसे ज्यादा संकट में हैं। इसकी वजह यह है कि मातृभाषाओं को बोलना भी तकनीक से प्रभावित हो रहा है और लेखन तो पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गया है। तकनीक की खासियत कहें या कमी, वह बाजार के लिहाज से खुद को विकसित करती है और अपने उत्पादों के लिए इसी नजरिए से शोध करती है। चूंकि मातृभाषाओं में कई ऐसी हैं, जिन्हें बोलने या जिनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बेहद कम है, इसलिए उनसे कमाई की संभावना कम है। चूंकि तकनीकी विकास में काफी धन लगता है, और मातृभाषाओं के एक हिस्से से कमाई की गुंजाइश नहीं दिखती, इसलिए तकनीक उनके सहज इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं दिखाती। इसलिए मातृभाषाओं की बड़ी संख्या लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत को ही देखिए। साल 1961 की जनगणना के आंकड़ों के लिहाज से भारत में 1652 भाषाएं थीं। लेकिन सिर्फ दस साल बाद यानी 1971 में यह संख्या घटकर महज 808 रह गई। ऐसा बदलाव तब हुआ, जब तकनीक का बोलबाला नहीं था। लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है। 2013 के भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण के अनुसार, विगत 50 वर्षों में 220 भाषाएँ जहां लुप्त हो गई हैं, वहीं 197 भाषाएँ खत्म होने की कगार पर हैं। मातृभाषाओं के लुप्त होने की कई अन्य वजहें भी हैं। भाषाशास्त्रियों के मुताबिक, व्यक्तिवादी दर्शन, उपभोक्तावाद, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों में आ रहे बदलाव, और शहरीकरण के साथ ही पारंपरिक मूल्यों के प्रति घटती निष्ठा और रोजगार के साधनों के रूप में भाषाओं की घटती संख्या भी मातृभाषाओं के खात्मे की वजह बना है। इसके बावजूद कुछ अपवादों को छोड़ दें तो मातृभाषाओं को लेकर कुछ इलाकों में सम्मोहन बरकरार है। शायद यही वजह है कि इस बार के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए यूनेस्को ने जो थीम रखा है, वह बेहद अहम जान पड़ता है। यह थीम है, 'भाषाओं का महत्व- रजत जयंती और सतत विकास'। इस थीम का ध्येय वाक्य 'अनेक भाषाएँ, एक भविष्य' है। पूर्वी बंगाल में 1952 में शहीद हुए भाषा आंदोलनकारियों की याद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की शुरूआत की पिछले साल यानी 2025 में रजत जयंती थी। तब यूनेस्को ने इस दिवस को भाषाई विविधता, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी शिक्षा के माध्यम से सतत विकास पर जोर देने पर केंद्रित किया था। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हर साल यूनेस्को किसी न किसी अहम विषय को ध्येय बनाता है और उस नजरिए से पूरे साल भाषाई विविधता को विकसित करने और उन्हें लागू करने पर जोर देता है। इस बार के ध्येय वाक्य से साफ है कि यूनेस्को चाहता है कि विश्व के सतत विकास में मातृभाषाओं की महत्ता को रेखांकित किया जाए। मातृभाषाएं एक तरह से भाषायी लोकतंत्र को रचती हैं। इस लोकतंत्र को बचाए बिना विविधरंगी संसार को नहीं बचाया जा सकता।

सोचिए, अगर उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और तकनीकी वर्चस्व की वजह से एक रस और एक भाषायी संसार तैयार हो जाए तो दुनिया कितनी नीरस होगी, ज्ञान के तमाम स्रोत तब या तो सूख चुके होंगे या फिर भुला दिए गए होंगे। इसलिए मातृभाषाओं को बचाना और उन्हें सांस्कृतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जिंदा रखना जरूरी हो जाता हैयूनेस्को की ओर से घोषित 'भाषाओं का महत्व रजत जयंती और सतत विकास' विषय, एक तरह से भाषायी विविधता, बहुभाषावाद और सतत विकास के बीच गहरे संबंधों को ही रेखांकित करता है। चूंकि यूनेस्को ने मातृभाषाओं को संरक्षित करने, भाषायी विविधता को जिंदा रखने और उन पर रश्क करने के साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है, इसलिए वह लगातार भाषाओं को बचाने का संदेश दे रहा है। दुनिया में इन संदेशों को सुना और समझा भी जा रहा है। चूंकि भाषाएँ सिर्फ संवाद का साधन ही नहीं होतीं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का अहम औजार भी हैं, लिहाजा प्राथमिक शिक्षा में उन पर जोर दिया जा रहा है। 2020 में आई भारत की नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषाओं में शिक्षा- विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। दुनियाभर के शिक्षाशास्त्री मानते हैं कि मातृभाषा आधारित शिक्षा समावेशी होती है और बच्चों की समझ को बेहतर बनाने में मददगार होती है। इतना ही नहीं, इसके चलते बच्चे की सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा के भी नतीजे बेहतर होते हैं। चूंकि सतत विकास में शिक्षा का स्थान अहम है और मातृभाषा आधारित शिक्षा बेहतरीन होती है, यही वजह है कि सतत विकास के लक्ष्यों को अब मातृभाषा के जरिए मिलने वाली शिक्षा में गंभीरता से खोजा जा रहा है। इसीलिए दुनिया एक बार फिर मातृभाषाओं के जरिए शिक्षा की ओर उन्मुख होती दिख रही है। जैसे-जैसे अधिकाधिक भाषाएँ विलुप्त होती जा रही हैं, भाषायी विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की 40 प्रतिशत आबादी को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जिन्हें वे बोलते या समझते हैं। मातृभाषाओं का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि स्थानीय समाज उनके जरिए शिक्षा हासिल कर सकें। मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक नींव की आधारशिला है। यह सोचने, समझने और संवाद करने का सबसे सहज माध्यम है, जो बच्चे को उसकी विरासत से जोड़ती है। मातृभाषा में शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है, संज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं, और दूसरी भाषाएं सीखना आसान हो जाता है। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे की अवधारणाओं को समझने की क्षमता तेज होती है और रचनात्मकता बढ़ती है। मातृभाषा संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का मुख्य माध्यम है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को मातृभाषा में सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, जिन बच्चों की नींव मातृभाषा में मजबूत होती है, मातृभाषाओं से इतर भाषाओं में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। मातृभाषाएं परिवार और समुदाय से एक मजबूत भावनात्मक संबंधों की गारंटी भी होती हैं। दुनिया की हर मातृभाषा अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की संवाहक है। इसी वजह स दुनियाभर के मानवशास्त्री मानते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भाषायी विविधता का संरक्षण जरूरी है। इतना ही नहीं, मातृभाषाएँ आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को भी बढ़ावा देती हैं, इस लिहाज से वे समावेशी समाज के निर्माण में भी सहायक मानी जाती हैं। मानवशास्त्रियों के अनुसार, स्थानीय भाषाएँ ज्ञान का खजाना हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इसीलिए यूनेस्को का मानना है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाषायी विविधता और बहुभाषावाद का उपयोग सहयोगी हो सकता है। इससे विश्व स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

## सम्पादकीय

### मदर ऑफ़ ऑल डील्स

**अमेरिका** ने टैरिफ कम कर दिया है। उसी ने बढ़ाया था, उसी ने कम कर दिया है। इस मामले में हमने कुछ नहीं किया है। बढ़ाना-घटाना, दोनों उसी ने किए हैं। हम तो बस हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। हम तो बस चूँ चूँ का मुरब्बा हैं। ये कहावतें यहाँ ठीक तो बैठ रही हैं ना! पहले कभी हमारे सामान पर अमेरिका औसतन तीन परसेंट टैरिफ लगाता था। यह पुरानी बात है। अब जब से ट्रंप जी दुबारा सरकार जी बने हैं तब से टैरिफ बढ़ाने की बात करते आ रहे हैं। कभी पचास प्रतिशत टैरिफ की बात करते थे तो कभी सौ प्रतिशत की। मुझे ध्यान आता है, एक बार तो पांच सौ प्रतिशत टैरिफ की बात भी कर दी थी। खैर अब अठारह प्रतिशत पर समझौता हो गया है। मदर ऑफ़ ऑल डील्स हो गई है। जब यह डील हुई, इसकी खबर हमें अमेरिका ने दी। कितने फख्र की बात है कि अब हमारे बारे में अमेरिका हमें बताता है। अमेरिका के सरकार जी हमें बताते हैं। पहले हमारे सरकार जी रात को आठ बजे स्वयं टीवी पर आ कर भाइयों और बहनों कहते थे, पर अब अमेरिका ङ्क या 'ट्रुथ' करता है। चलो यह डील तो हमारे और अमेरिका के बीच थी, अमेरिका ने बता भी दी तो कोई बात नहीं। हम बताएं, अमेरिका बताये, एक ही बात है। पर हमारे और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने जा रहा है, यह बात भी हमें ट्रंप जी ने ही बताई थी। और सिर्फ बताई ही नहीं थी, यह भी कहा था कि यह युद्ध विराम मैंने ही करवाया है। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं कहा, अब तक सत्तर अस्सी बार तो कह ही दिया होगा। अब मैं सोचता हूं, अगर नोटबंदी और लॉकडाउन की खबर भी अमेरिकी सरकार जी ने दी होती तो कितना अच्छा होता। हमारे सरकार जी नोटबंदी और लॉक डाउन के पाप से बच जाते। जहाँ तक कहने की बात है, ट्रंप जी तो जो मर्जी कह देते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं सची थी या झूठी, जिसमें ट्रंप जी कह रहे थे कि...। चलो छोड़ो, जाने भी दो। ट्रंप जी भी हमारे सरकार जी की तरह ही हैं। बिना सोचे समझे, जो मर्जी कह देते हैं। अब कोई किसी का पोलिटिकल करियर कैसे खत्म कर सकता है भला। और वह भी वाशिंगटन वाला नई दिल्ली वाले का। जरूर ही एआई द्वारा बनाई गई वीडियो होगी। मैंने तो जब देखी थी, तभी शक हो गया था। हमारे सरकार जी और ट्रंप जी दोस्त हैं। बड़े वाले दोस्त। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई वाले दोस्त। 'यूँ ही नहीं दिल लुभाता कोई वाले दोस्त। हमारे सरकार जी तो सभी से पहले का नाता वाला सम्बन्ध मानते हैं। तो ट्रंप जी जब दूसरी बार ट्रंप बने तो वे अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने के लिए बने। और हमारे सरकार जी तो हमारे देश को विश्व गुरु बना ही रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं है। 2014 से बना रहे हैं और 2047 तक बना ही डालेंगे। अब तो जो भी वायदा होता है, 2047 का ही होता है। उनके पास बहुत समय है। पर ट्रंप जी के पास समय कम है। तीन साल से भी कम समय बचा है ट्रंप जी के ट्रंप बने रहने के लिए। तो उन्हें इन्हीं तीन सालों में अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है। तो एक दिन ट्रंप जी, दोस्ती दोस्ती में हमारे सरकार जी से बोले, यार मैं तेरे देश पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है। हमारे सरकार जी चिंतित हो गए।

# उत्तर प्रदेश में भाजपा का राजनीतिक ग्राफ

उत्तर प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है बल्कि यह देश की संसद में सर्वाधिक 80 लोकसभा सदस्य भेजने वाला राज्य भी है। इसी वजह से कहा जाता है कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार बनाने का रास्ता इस राज्य की राजधानी लखनऊ से होकर ही गुजरता है। मगर भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन से लेकर आजादी के बाद तक इस राज्य की राष्ट्रीय राजनीति में केन्द्रीय भूमिका भी रही है। चाहे वह कांग्रेस पार्टी का अहिंसक सत्याग्रह आन्दोलन हो या क्रान्तिकारियों का सशस्त्र संघर्ष सभी में इस प्रदेश के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसी राज्य के वाराणसी व इलाहाबाद (प्रयागराज) शहरों से भारतीय दर्शन से लेकर सांस्कृतिक चेतना की धारा बहती रही है। मध्य युगीन भक्ति आन्दोलन से लेकर सुल्तानी व बादशाही दौर तक में यह राज्य पूरे भारत के लिए हिन्दू सांस्कृतिक व धार्मिक चेतना का प्रेरणास्रोत बना रहा है। भारत के हिन्दी साहित्य में भी इस प्रदेश का योगदान अतुलनीय रहा है अतः स्वतन्त्रता के बाद की राजनीति में इस प्रदेश में जिस प्रकार राष्ट्रवादी सोच पर आधारित जनसंघ (भाजपा) की राजनीति को आधार मिला उसके बहुआयामी कारण रहे। यह आश्चर्य हो सकता है कि देश के 1952 में हुए प्रथम आम चुनावों में इस प्रदेश से जनसंघ का एक भी प्रत्याशी नहीं चुना गया और इसके तीनों सांसद प. बंगाल व राजस्थान से चुन कर आये। इनमें से दो प. बंगाल से थे और एक राजस्थान से। प. बंगाल की एक सीट पर जनसंघ के संस्थापक स्व. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं थे। परन्तु 1957 के चुनावों से लेकर आज तक जनसंघ का नया स्वरूप भाजपा लगातार प्रगति करती रही और अब हालत यह है कि 2017 से उसकी राज्य में अपने दम पर सरकार काबिज है। इस प्रदेश की राजनीति में वर्ष 1992 से गुणात्मक अन्तर आना शुरू हुआ। इस अन्तर का आकर्षण इतना गहरा था कि देश के अन्य उत्तर- पश्चिम राज्यों में भी भाजपा का वह विमर्श राजनीति का केन्द्र बना जो उत्तर प्रदेश से ही निकला था। यह विमर्श अयोध्या में श्री राम मन्दिर निर्माण आन्दोलन से उपजा था जिसके जनक तत्कालीन भाजपा नेता श्री लाल कृष्ण अडवानी थे। अडवानी जी ने उस समय अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण का विमर्श विश्व हिन्दू परिषद के हाथ से छीना था क्योंकि उस समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम जन्मभूमि मन्दिर बनाने का बीड़ा इसके अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया व महासचिव बाबू दाऊदयाल खन्ना लिये हुए थे। श्री अडवानी ने इसे भाजपा के मंच से आवाज देकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का राग अलापा और देखते-देखते ही उनका आन्दोलन जन आन्दोलन में परिवर्तित होने लगा जिसे बाद में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय आन्दोलन की संज्ञा दी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस आन्दोलन ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया और दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य पर भी दस्तक दे दी। लेकिन इससे पहले ही 1967 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और इसे प्रमुख विपक्षी दल का रुतबा हासिल हो चुका था। 1967 के विधानसभा चुनावों में जनसंघ की कुल 101 सीटें (दो निर्दलीयों के शामिल होने के बाद) आयी थीं और कांग्रेस को किनारे पर ही बहुमत मिला था मगर इस पार्टी से तब स्व. चौधरी चरण सिंह ने विद्रोह कर दिया था और 14 विधायकों के साथ वह कांग्रेस से बाहर आ गये थे।

इससे विधानसभा में कांग्रेस अल्पमत में रह गई थी और समाजवादी नेता स्व. डा. राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के आह्वान के चलते राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी संयुक्त विधायक दल (संविद) की सरकार का गठन हुआ था। हालांकि यह सरकार कांग्रेस से निकले स्व. चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में ही गठित हुई थी मगर इस सरकार में कम्युनिस्ट भी शामिल थे और जनसंघ भी। संविद में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से जनसंघ के नेता स्व. रामप्रकाश गुप्ता को उप मुख्यमन्त्री पद दिया गया और उन्हें शिक्षा मन्त्रालय दिया गया। मगर यह सरकार आन्तरिक मतभेदों के चलते ज्यादा दिन नहीं चल सकी और अगले साल ही गिर गई। इसके अगले साल 1969 में राज्य में मध्यावधि चुनाव घोषित कर दिये गये। इस वर्ष से राज्य की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। इस साल स्व. चरण सिंह ने अपनी नई पार्टी भारतीय क्रान्ति दल के गठन की घोषणा की और सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। चरण सिंह चूंकि मूलतः ग्रामीण व किसान नेता थे अतः उनके साथ राज्य की सभी खेतीहर जातियों के मतदाताओं ने स्वयं को जोड़ा और जनसंघ के विशुद्ध हिन्दू मूलक राष्ट्रवाद से स्वयं को इसलिए छिटकाया क्योंकि चरण सिंह राजनीति में ग्रामीणों की समस्याओं को केन्द्र में ले आये थे। चरण सिंह कह रहे थे कि भारत का सर्वांगीण विकास केवल गांधीवादी आर्थिक दर्शन अपनाने से ही हो सकता है जिसके लिए विकास की उस धारा को पलटना होगा जो कि देश में बड़े- बड़े उद्योग स्थापित करके शहरों को पूंजी केन्द्र बना कर बह रही है। चरणसिंह ने विशुद्ध आर्थिक पक्ष को पकड़कर गांवों के विकास की विचारधारा को स्थापित किया और सम्पूर्ण ग्रामीण जगत को धर्म व जाति के निरपेक्ष एक झंडे के नीचे लाने का भगीरथ प्रयास किया इससे सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस व जनसंघ को हुआ। एक तरफ कांग्रेस का खेतीहर जातियों का वोट बैंक बिखर गया और दूसरी तरफ जनसंघ का गांवों में पैठ बनाने का स्वप्न टूट गया। बेशक इन 1969 के चुनावों मे जनसंघ ने हवा का रुख देखते हुए यह नारा दिया था

हर हाथ को काम, हर खेत को पानी
घर-घर में दीपक जनसंघ की निशानी

मगर ग्रामीण इलाकों से जनसंघ को समर्थन नहीं मिल पाया और इस वर्ष हुए चुनावों में इसकी विधायक संख्या घट कर 49 रह गई जबकि चौधरी साहब के भारतीय क्रान्ति दल के 117 विधायक बन गये। इसके बाद के वर्षों में राज्य की राजनीति में बहुत उतार-चढ़ाव आये जिनमें 1971 में स्व. इन्दिरा गांधी की कांग्रेस के विजय अभियान से लेकर 1977 में जनता पार्टी की उल्टी पटखनी भी शामिल है मगर 1992 में राम मन्दिर आन्दोलन से भाजपा का जो विजय अभियान शुरू हुआ था वह निर्बाध रूप से इस हकीकत के बावजूद जारी रहा कि इस बीच में स्व. मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी व बहिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद भी भाजपा अपना आकर्षण नहीं खो सकी। वर्तमान में राज्य में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार 2017 से काबिज है। इस सरकार को राज्य में कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के लिए व हिन्दुत्व मूलक राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की जातिमूलक अल्पसंख्यक या मुस्लिम परक राजनीति के चलते भाजपा अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि केवल कुछ विशेष ग्रामीण जातियों को छोड़कर भाजपा के साथ गांवों की श्रम परक जातियों के लोगों का जुड़ाव गहरा हुआ है। यह जुड़ाव पिछड़ों में भी अति पिछड़े कहे जाने वाले लोगों का है जबकि दलित जातियों में गैर रैदासी कही जाने वाली जातियों का है। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान ऐसी चुनौती आ सकती है कि विश्व विद्यालयों के युवा वर्ग में जातिगत आधार पर जो बंटवारा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के नये निर्देशों की वजह से हुआ है उसके बढ़ते प्रभाव को रोका जाये। फिलहाल तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन निर्देशों पर रोक लगा दी है मगर इससे भाजपा के उस वोट आधार में बेचैनी शुरू हो गई है जो 1992 के बाद से इससे जुड़ा है। जाहिर है कि यह दौर 1969 का नहीं है क्योंकि राजनीति का कलेवर वर्तमान में पूरी तरह बदल चुका है परन्तु इससे नये सिरे से जातिवाद के सिर उठाने का खतरा तो मंडरा तो रहा ही है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

# 'टैरिफ ले नहीं सकता, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता हूं', कोर्ट के फैसले पर बोले ट्रंप

**वॉशिंगटन** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी से टैरिफ नहीं ले सकते, लेकिन वह किसी भी देश के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर सकते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों को गलत तरीके से खारिज किया है, उनकी जगह लेने के लिए दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पास विकल्प हैं, बहुत अच्छे विकल्प हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। हम ज्यादा पैसा हासिल करेंगे और इससे हम और ज्यादा मजबूत बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द करने के फैसले के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने का एलान कर दिया। ट्रंप ने धारा 122 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वैश्विक 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति 150 दिनों तक 15 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाया है। 150 दिनों के बाद अमेरिकी संसद में प्रस्ताव लाकर इसे आगे जारी रखने या न रखने पर फैसला किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'आपको यह दिखाने के लिए कि यह फैसला कितना बेकार है, कोर्ट ने कहा कि मुझे एक डॉलर भी शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है। मैं एक डॉलर भी नहीं ले सकता।

यह फैसला जरूर उन दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए लिया गया होगा, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, जिसकी रक्षा उन्हें करनी चाहिए। यही उनका काम है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास उन देशों के साथ किसी भी तरह का व्यापार या कारोबार पूरी तरह बंद करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, वह व्यापार को खत्म कर सकते हैं। वह उस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकते हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौन-सा लाइसेंस कभी बिना शुल्क लिए जारी किया गया है? जब आप लाइसेंस जारी करते हैं तो आप शुल्क लेते हैं। यह अपने-आप होता है, लेकिन इस कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है।

# बांग्लादेश नवनिर्वाचित सांसदों का लेखा-जोखा: 43 सदस्यों पर हत्या के आरोप, 187 माननीय करोड़पति

**ढाका** बांग्लादेश में हाल ही में हुए 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में चुने गए 43 सांसदों (एमपी) पर हत्या के मामले दर्ज हैं। यह जानकारी देश के प्रमुख नागरिक संगठन सुशासन के लिए नागरिक (शुजन) द्वारा जारी आंकड़ों के हवाले से स्थानीय मीडिया ने दी है।

ढाका के प्रमुख अखबार दे डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, 42 सांसद पहले से ऐसे मामलों का सामना कर चुके थे, जबकि 12 सांसदों पर पुराने और वर्तमान दोनों प्रकार के मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमुख राजनीतिक दलों में सबसे अधिक मौजूदा आपराधिक मामलों का प्रतिशत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सांसदों में है, जिसने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी के 50.24 प्रतिशत सांसदों पर वर्तमान में मामले चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर कट्टरपंथी बांग्लादेश जमात ए इस्लामी है, जिसके 47.07 प्रतिशत सांसदों पर मौजूदा मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर 142 सांसदों पर इस समय कानूनी मामले लंबित हैं, जबकि 185 सांसद अतीत में मामलों का सामना कर चुके हैं। करीब 95 सांसद ऐसे हैं, जिन पर पहले भी और वर्तमान में भी मामले दर्ज हैं। शुजन के मुख्य समन्वयक दिलीप कुमार सरकार ने ढाका में 'नवनिर्वाचित सांसदों के हलफनामे की जानकारी का विश्लेषण' कार्यक्रम में यह विस्तृत आंकड़ा प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12वें चुनाव की तुलना में विजेताओं के खिलाफ कानूनी मामलों में वृद्धि हुई है। 297 निर्वाचित सांसदों में से केवल आठ के पास पीएचडी डिग्री है। 138 के पास स्नातकोत्तर, 93 स्नातक, 20 ने उच्च माध्यमिक (एचएससी) और 17 ने माध्यमिक (एसएससी) तक शिक्षा प्राप्त की है। 297 सांसदों में से 182 (61.28 प्रतिशत) व्यवसाय से जुड़े हैं, जो पिछले चुनाव के 66.89 प्रतिशत से कुछ कम है। 36 सांसद वकील हैं, 22 शिक्षक हैं, 13 कृषक हैं और आठ ने राजनीति को अपना पेशा बताया है। पांच सरकारी/निजी सेवा में रहे हैं, जबकि 27 अन्य पेशों से जुड़े हैं। संपत्ति घोषणाओं के अनुसार, 271 सांसदों की संपत्ति एक करोड़ टका से अधिक है, जबकि 187 सांसदों की संपत्ति पांच करोड़ टका से ज्यादा है।बीएनपी के 209 सांसदों में से 201 की संपत्ति एक करोड़ टका से अधिक है, जबकि जमात के 68 सांसदों में से 52 इस श्रेणी में आते हैं। विश्लेषण के मुताबिक, संपन्न उम्मीदवारों के जीतने की संभावना अधिक रही। जहां कुल उम्मीदवारों में 55.63 प्रतिशत करोड़पति थे, वहीं निर्वाचित सांसदों में यह अनुपात और अधिक है।

# ट्रंप ने टैरिफ को बनाया प्रमुख मुद्दा, अब 'सुप्रीम' फैसले से अमेरिका में बढ़ सकती है अराजकता

**वाशिंगटन ।** राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर अकेले चलने की कीमत चुकानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले से चुनाव वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक अराजकता और अनिश्चितता और बढ़ जाएगी।

ऐसा इसलिए क्योंकि अभी यह पता नहीं है कि वसूला गया टैरिफ वापस होगा या नहीं। वहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है कि देशों पर लगे टैरिफ की भविष्य में क्या स्थिति होगी। हर 10 में से 6 अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप ने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर सारी हद पार कर दी है। वहीं, ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि फैसला शर्मनाक है। उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ट्रंप ने फैसले की जानकारी मिलते ही कहा, मुझे इन अदालतों के बारे में कुछ करना होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखेंगे। रिपब्लिकन रणनीतिकार डग हेये ने फैसले के बाद कहा, राष्ट्रपति इस फैसले से खुश नहीं होंगे। हम यह सुनने लगे हैं कि यह एक बड़ा झटका है। लेकिन निश्चित रूप से

ट्रंप दूसरे रास्ते तलाश करने की कोशिश करेंगे।

हेये ने पूछा, क्या वे इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। व्हाइट हाउस वैकल्पिक कानूनों का इस्तेमाल करके टैरिफ को बरकरार रखने की योजना बना रहा है, लेकिन इनके जरिये केवल बहस ही लंबी होगी और उन मुद्दों को जीवित रखेंगी जो मतदाताओं के बीच काफी अलोकप्रिय हैं। अमेरिकी नागरिकों की महंगाई संबंधी चिंताओं को दूर करने के वादे पर चुने गए राष्ट्रपति के लिए अधिक चिंताजनक बात यह है कि पिछले अप्रैल में किए गए एक सर्वेक्षण में 76 प्रतिशत लोगों का मानना था कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों से अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। ट्रंप द्वारा आक्रामक रूप से टैरिफ लगाने से कई रिपब्लिकन सांसदों में सार्वजनिक और निजी तौर पर बेचैनी पैदा हो गई है। राष्ट्रपति की पार्टी के कम से कम सात सीनेटरों ने समय-समय पर इसे लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। इस महीने की शुरुआत में, छह हाउस रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कनाडा पर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस फैसले से ट्रंप के आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि उन्होंने कानून तोड़ा और परिणामस्वरूप मध्यमवर्गीय परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल, मुक्त व्यापार रिपब्लिकन पार्टी का प्रमुख सिद्धांत रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता, संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण और मुक्त व्यापार की जीत बताया। पेंस ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिकी परिवार और अमेरिकी व्यवसायी इस टैरिफ का भुगतान करते हैं - विदेशी देश नहीं। इस फैसले से अमेरिकी परिवार और व्यवसाय राहत की सांस ले सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए व्यापक टैरिफ को रद्द करने के फैसले का भारतीय निर्यातकों ने स्वागत किया है। निर्यात संगठनों का कहना है कि इस निर्णय से उन भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो देश-विशेष शुल्क से प्रभावित थीं। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि इस फैसले से भारत-अमेरिका व्यापार में स्थिरता आएगी और भविष्य को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी।

## पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना की कार्रवाई, ड्रग तस्करी में शामिल एक और नाव ध्वस्त; तीन की मौत

**वॉशिंगटन ।** अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक और नाव पर हमला किया है, जिस पर ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप था। इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के साउदर्न कमांड के मुताबिक, यह नाव उन रास्तों से गुजर रही थी जिन्हें ड्रग तस्करी के लिए जाना जाता है। सेना का दावा है कि नाव नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में नाव पहले समुद्र में तैरती दिखती है और फिर अचानक विस्फोट के साथ आग लग जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका के ड्रग कार्टेल के साथ सशस्त्र संघर्ष में है। इन हमलों को उन्होंने ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम बताया है। वहीं, आलोचकों और विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए हैं और कहा कि ट्रंप सरकार ने यह साबित करने के लिए कम सबूत दिए हैं कि मारे गए लोग नार्को-टेररिस्ट थे। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका में फैलने वाला खतरनाक ड्रग फेंटेनाइल ज्यादातर जमीन के रास्ते मेक्सिको से आता है, समुद्र से नहीं। पहले हमले में घायल बचे लोगों पर दोबारा हमला करने की घटना के बाद इसे कानूनी और नैतिक रूप से गलत बताया गया। एक तरफ जहां रिपब्लिकन नेताओं ने इसे कानूनी और जरूरी कार्रवाई बताया। वहीं डेमोक्रेटिक नेताओं और कानून विशेषज्ञों ने इसे हत्या या युद्ध अपराध तक कहा।

# लेबनान में इस्राइली हमलों से 12 की मौत, बच्चों समेत 24 घायल; क्षेत्रीय तनाव और गहराया

**बेरूत** मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। लेबनान के पूर्वी बेका घाटी में इस्राइल के हवाई हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। घायलों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।

उसी दिन सैदा शहर के एक फलस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हुए अलग हमले में दो और लोगों की जान गई। इन घटनाओं से क्षेत्र में हालात और संवेदनशील हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को बेका घाटी में कई ठिकानों पर हवाई हमले हुए। स्थानीय टीवी फुटेज में एक बहुमंजिला इमारत को निशाना बनते दिखाया गया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई और राहत टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश करती रहीं। इस्राइली सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की ओर से तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। दिन में पहले सैदा के ऐन अल-हिलवेह फलस्तीनी शरणार्थी शिविर पर भी हमला हुआ। इस्राइल ने कहा कि उसने हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हमास ने दो सदस्यों की मौत की पुष्टि की, लेकिन कहा कि कमांड सेंटर पर हमले का दावा कमजोर बहाना है। संगठन ने कहा कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया वह विभिन्न फलस्तीनी गुटों की संयुक्त सुरक्षा इकाई की थी। अक्तूबर 2023 में हमास के नेतृत्व में इस्राइल पर हुए हमले के बाद गाजा में युद्ध शुरू हुआ। इसके समर्थन में हिजबुल्लाह ने लेबनान से इस्राइल पर रॉकेट दागे। जवाब में इस्राइल ने हवाई हमले और गोलाबारी की। सितंबर 2024 में यह टकराव व्यापक युद्ध में बदल गया। दो महीने बाद अमेरिका की मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ, लेकिन पूरी तरह शांति बहाल नहीं हो सकी। तब से इस्राइल लेबनान में नियमित हमले करता रहा है। शुक्रवार के हमलों में मौतों की संख्या असामान्य रूप से अधिक रही। यह उस समय हुआ है जब अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास का समर्थक माना जाता है। लेबनान में आशंका है कि यदि इस्राइल और ईरान के बीच नया संघर्ष छिड़ता है तो देश फिर से बड़े युद्ध में खिंच सकता है।

# पीएम मोदी के दौरे से उत्साहित इस्राइल, नेतन्याहू बोले- भारत बेहद शक्तिशाली और लोकप्रिय देश

**नई दिल्ली ।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से उत्साहित उनके इस्राइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत बेहद शक्तिशाली और लोकप्रिय देश है। इस्राइल अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन मजबूत कर रहा है। नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को इस्राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) के कैडेट के दीक्षांत समारोह में कहा, इस्राइल बुराई के खिलाफ निवारक उपाय करता है। इसलिए, क्षेत्र में खतरों को बेअसर करने के लिए आवश्यकतानुसार, समय-समय पर कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने कहा, हम अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाएंगे। अगले सप्ताह एक बेहद शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री इस्राइल का दौरा करेंगे। नेतन्याहू ने कहा, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैं एक और महत्वपूर्ण दौरे से लौटा हूं। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद से मेरा सातवां दौरा था। वहां मैंने इस्राइल के सबसे पक्के मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि हाल में प्रकाशित अमेरिकी सुरक्षा सिद्धांत में इस्राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश

है जिसे अमेरिका आदर्श सहयोगी बताता है।

मालूम हो कि पीएम मोदी के इस्राइल दौरे की वैश्विक स्तर पर चर्चाएं है। नेतन्याहू ने इससे पहले रविवार को प्रमुख अमेरिकी-यहूदी संगठनों के अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित यात्रा का उल्लेख किया था। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था, संसद को संबोधित करने की तैयारी चल रही है। अगले हफ्ते यहां कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी। नेतन्याहू ने कहा, वर्षों से इस्राइल और भारत के बीच एक मजबूत गठबंधन है। हम हर तरह के सहयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, भारत कोई छोटा देश नहीं है। इसकी आबादी 1.4 अरब है। भारत बेहद शक्तिशाली और बेहद लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर इस्राइल पहुंचेंगे। इस दौरान वह नेसेट (संसद) को संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। यह पीएम मोदी की इस्राइल की दूसरी यात्रा होगी। पहली यात्रा जुलाई 2017 में हुई थी, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यहूदी राष्ट्र की पहली यात्रा थी।

# भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस का वार, कहा- ये डील नहीं देश के लिए परेशानी

**नई दिल्ली ।** अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति को नहीं है। इस फैसले के बाद भारत की राजनीति में भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने इसे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम व्यापार समझौता दरअसल देश के लिए ओरडील यानी परेशानी साबित हो रहा है। पार्टी का कहना है कि यह समझौता मजबूरी और जल्दबाजी में किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि भारत सरकार थोड़ा इंतजार करती और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने देती, तो शायद भारत को एकतरफा शर्तों वाले समझौते का सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि बचाने और राजनीतिक दबाव से निकलने के लिए जल्दबाजी में यह समझौता किया। पार्टी का दावा है कि इससे भारतीय किसानों और देश के आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस व्यापार समझौते को संतुलित नहीं, बल्कि दबाव में किया गया फैसला बता रही है। उन्होंने अमेरिकी न्याय व्यवस्था की सराहना भी की। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि दो फरवरी 2026 की रात अमेरिका द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा अचानक कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा में उसी दिन दोपहर क्या हुआ था, जिससे प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस से घोषणा करवानी पड़ी। कांग्रेस का दावा है कि यह समझौता भारत के किसानों और देश की संप्रभुता के लिए नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ डील जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा।

# मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जनसुनवाई ऐप किया लॉन्च, 15 दिन में शिकायतों का होगा निस्तारण

**नई दिल्ली ।** दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की शिकायतों के तेज और पारदर्शी समाधान के लिए 'सीएम जन सुनवाई पोर्टल' और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है. सरकार का कहना है कि अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे घर बैठे अपने मोबाइल से ही शिकायत दर्ज कर सकेंगे.

**मिलेगी कई तरह की सुविधाएं**

इस पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों से संबंधित शिकायतें भी ऑनलाइन की जा सकेंगी. पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सरकार की करीब 75 सेवाओं का लाभ भी ऑनलाइन लिया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सेवाओं को अब सीएससी (कॉमन सर्विस

सेंटर) से भी जोड़ा गया है, ताकि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे भी आसानी से इन सेवाओं का लाभ ले सकें. डिजिटल सेवा पोर्टल को भी इससे जोड़ा गया है, ताकि नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतर सरकारी सेवाएं एक ही मंच पर सरल तरीके से उपलब्ध हो सकें.

**15 दिनों में समाधान का वादा**

दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि हर शिकायत का 15 दिनों के अंदर समाधान किया जाएगा. शिकायतकर्ता को उसके मोबाइल पर ही अपडेट मिलता रहेगा, जिससे उसे बार-बार पूछताछ करने की जरूरत नहीं होगी. अगर किसी स्तर पर देरी होती है तो उसकी भी निगरानी की जाएगी.

**पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर**

मुख्यमंत्री का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी. अब हर शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी और उसकी स्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा. इससे संबंधित विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी. किस अधिकारी के पास मामला लंबित है और कितने समय से लंबित है, इसकी पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज रहेगी.

**कांग्रेस पर साधा निशाना**

युवा कांग्रेस के हालिया प्रोटेस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि जब देश तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब इस तरह के प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं.

## एआई समिट में हंगामा- सुधांशु त्रिवेदी ने यूथ कांग्रेस को बताया लश्कर-ए-राहुल, बोले- देश कभी माफ नहीं करेगा

**नई दिल्ली ।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-राहुल के झंडाबरदार भारत की इजत को तार-तार करने में लगे हुए हैं। इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। सुधांशु त्रिवेदी ने एक वीडियो संदेश में कहा, विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, ये सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कहकर छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा, ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ते-तोड़ते कांग्रेस पार्टी आज उस स्थिति में पहुंच गई है, जहां राजनीति और राष्ट्र के विरोध की सीमा समाप्त होती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के मन में शायद आज भी भारत की वह छवि है, जब भुखमरी थी और लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे। भारतीयों की अर्धनग्न तस्वीरें ही दिखाई जाती थीं। इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर वही पुराने भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का प्रयास किया, जो निंदनीय है। यूथ कांग्रेस को लश्कर-ए-राहुल बताते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा, अभी तक राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब लश्कर-ए-राहुल के सिपाही भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की आधुनिकतम तकनीक एआई में भारत अग्रिम भूमिका में दिखाई पड़ रहा है, तो कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

## सुप्रीम कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन में असमानता पर जताई चिंता, जारी किए देशव्यापी निर्देश

**नई दिल्ली ।** सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन में असमान स्थिति पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा क्रियान्वयन खामियों के रहते आज की पीढ़ी आगे के विधायी सुधारों का इंतजार नहीं कर सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने देशभर में 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रहे ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 को लागू कराने के लिए कार्यपालिका के पास आवश्यक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि नगरपालिका ठोस कचरे की उपेक्षा से अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी उतना ही असर पड़ेगा और जब दुनिया प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों में देश की ओर देखती है तो भारत को 2026 के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्रोत पर पृथक्करण और बुनियादी ढांचे की ठोस तैयारी के बिना उच्च परिणाम की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है। कचरा-मुक्त भारत सुनिश्चित करना हर हितधारक का दायित्व है। अदालत ने पार्षदों, महापौरों, अध्यक्षों, निगम पार्षदों और वार्ड सदस्यों को स्रोत पर कचरा पृथक्करण शिक्षा के लिए लीड फैसिलिटेटर नामित करते हुए कहा कि अपने-अपने वार्ड में प्रत्येक नागरिक को 2026 के नियमों के क्रियान्वयन से जोड़ना उनका वैधानिक दायित्व है। जिला कलेक्टरों के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन अवसंरचना का ऑडिट कराने और चिन्हित समस्याओं तथा उठाए गए कदमों की सूचना समयबद्ध तरीके से मुख्य सचिव को देने का निर्देश दिया गया। अदालत ने कहा कि प्रत्येक स्थानीय निकाय 100 प्रतिशत अनुपालन की समय-सीमा तय कर उसकी जानकारी सार्वजनिक करे। जिला कलेक्टरों को निगमों, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन की स्थापना, क्रियान्वयन और संचालन की निगरानी का अधिकार दिया गया है तथा किसी भी गैर-अनुपालन की रिपोर्ट राय और केंद्र स्तर पर संबंधित विभागों को भेजी जाएगी। स्थानीय निकायों को अनुपालन रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफिक साक्ष्य ईमेल के जरिए जिला कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वास्तविक प्रगति का सत्यापन हो सके। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चार-स्तरीय पृथक्करण व्यवस्था (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल) के लिए आवश्यक अवसंरचना की पहचान कर उसे शीघ्र चालू कराने को कहा गया है।

# दिल्ली सरकार ने जारी किया एक साल रिपोर्ट कार्ड, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर बोला हमला

**नई दिल्ली ।** दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई. इस मौके पर उन्होंने जहां एक तरफ आगे के एजेंडे का ऐलान किया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना भी साधा. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार को सफल एक वर्ष पूरा करने पर बधाई दी और आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम की शुरुआत लड्डू खिलाकर जश्न के साथ हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष को सरकार की पहली वर्षगांठ की बधाई दी गई. सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने संकल्प लिया था कि झाड़ू से कचरा बाहर निकालना है और कमल के रंगों से विकास की रंगोली सजानी है. उन्होंने दावा किया कि 8 फरवरी 2025 को यह संकल्प पूरा हुआ और 27 वर्षों बाद दिल्ली को बीजेपी की संवेदनशील सरकार मिली, जिसके जनता दरबार आम नागरिकों के लिए हमेशा खुले हैं.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों से दिल्लीवासियों को अवगत कराया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका दायित्वबोध है. यह सरकार जिम्मेदारी लेती है, हर मुद्दे पर जवाबदेह है और आगे भी रहेगी. सचदेवा ने आरोप लगाया कि पिछले तीन दशकों में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की सरकारों ने दिल्ली की सीवर व्यवस्था को ठप कर दिया था. उन्होंने कहा कि किराड़ी जैसी नई कॉलोनियों में सीवर लाइन और सफाई के नाम पर घोटाले हुए, जिसके कारण हल्की बारिश में भी दिल्ली जलमग्न हो जाती थी. बीजेपी सरकार ने पहले ही वर्ष में इस स्थिति को नियंत्रित किया और बीते मॉनसून में हालात में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला. उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लगभग ठप हो गई थी. बीजेपी सरकार ने एक ही वर्ष में करीब 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्लीवासियों को उपलब्ध कराईं, जिससे परिवहन सेवाओं में सुधार हुआ है और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी कदम बढ़ा है. सचदेवा ने कहा कि पूर्व सरकार ने दिल्ली को मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर घोटाला दिया. इसके विपरीत मौजूदा सरकार ने 100 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, जहां लोगों को प्राथमिक जांच और उपचार की समग्र सुविधा मिल रही है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने हाल ही में 25 अटल कैंटीन आम नागरिकों को समर्पित की हैं. अब राजधानी में कुल 71 नई कैंटीन संचालित हो रही हैं और शीघ्र ही इनकी संख्या 150 के पार पहुंचाने की तैयारी है, जिससे जरूरतमंदों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध होगा. सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए सरकार ने होली से गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है. इसके साथ ही मातृत्व योजना की राशि में वृद्धि कर एक और संकल्प को साकार किया गया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचदेवा ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लगभग एक वर्ष तक सार्वजनिक रूप से लापता रहने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दिल्लीवासियों को चौंका दिया है. सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में रहते हुए वह मंत्री कम और उगाही निरीक्षक यादा थे और अब पंजाब में सक्रिय हैं.

# एआई समिट में हंगामे पर बवाल- दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन

**नई दिल्ली ।**

भारत मंडपम में आयोजित India AI Impact Summit के दौरान यूथ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किए गए प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय (24 अकबर रोड) के बाहर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मान सिंह रोड गोलचक्कर से कांग्रेस कार्यालय तक मार्च निकाला। बीजेपी नेताओं ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को हुड़दंग करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। प्रदर्शन स्थल पर मीडिया से बात करते हुए दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, आज हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता स्वेछा से यहाँ जुटे हैं। जब पूरा देश एआई समिट के आयोजन पर गर्व महसूस कर रहा है, तब राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक हताशा दिखाने के लिए इस वैश्विक आयोजन में बाधा डाली। देश उन्हें इस कृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेगा। वीरेंद्र सचदेवा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समिट वेन्यू पर shirtless होकर प्रदर्शन करने वाले लोग असली कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, बल्कि किराए के गुंडे थे। उन्होंने कहा, एक तरफ देश का युवा पीएम मोदी के नेतृत्व में एआई के क्षेत्र में नवाचार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के इशारे पर कुछ लोग भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रल्हाद जोशी (केंद्रीय मंत्री)- उन्होंने कर्नाटक में बयान देते हुए मांग की कि एआईसीसी अध्यक्ष को इस शर्मनाक व्यवहार के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

अनिल राजभर (यूपी मंत्री)- उन्होंने इसे गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वैश्विक प्रतिनिधि भारत की एआई शक्ति देख रहे थे, तब ऐसा व्यवहार राष्ट्रहित के खिलाफ है। यह राजनीतिक टकराव तब शुरू हुआ जब शुक्रवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर विरोध दर्ज कराया था। बीजेपी इसे वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करने की साजिश बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे अपनी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति कह रही है।

# प्रशासनिक न्यायाधीश ने किया ई-सेवा केन्द्र का उद्घाटन

मुरादाबाद।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी शनिवार को महानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद जिला न्यायालय में ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन कर विधिक जागरूकता वाहन को रवाना किया। उन्होंने 22 फरवरी को पंचायत भवन में आयोजित होने वाले मेगा विधिक सेवा शिविर के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया। इलाहाबाद उ'च न्यायालय के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मुरादाबाद जिला न्यायालय परिसर में नए ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने अदालत परिसर में पौधरोपण करते हुए विधिक

## डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगीः न्यायमूर्ति नीरज तिवारी

जागरूकता वाहन (न्याय रथ) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शनिवार को उद्घाटन समारोह में न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुलभ और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में ई-सेवा केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। इससे वादकारियों और

अधिवक्ताओं को मुकदमों की स्थिति, आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि, ऑनलाइन सेवाएं और अन्य न्यायिक सुविधाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों का समय बचेगा। इससे पहले उन्होंने कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। कार्यक्रम के दौरान जिला जज सै. माऊज बिन आसिम ने न्यायमूर्ति तिवारी का स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किया। कार्यक्रम में जनपद के न्यायिक अधिकारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।

न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दि बार एसोसिएशन एण्ड लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान अध्यक्ष आनन्द मोहन गुप्ता एवं महासचिव कपिल गुप्ता की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। बता दे कि 22 फरवरी को पंचायत भवन में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ भी न्यायमूर्ति नीरज तिवारी करेंगे। जनपद न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के मार्गदर्शन में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी के निर्देशन में तहसील कांठ, सदर, ठाकुरद्वारा और बिलारी में प्री-कैंप आयोजित किए गए। प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने बताया कि मेगा शिविर में आम जनता को निशुल्क विधिक सहायता, योजनाओं की जानकारी और ऑनलाइन सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। शनिवार सुबह न्यायालय परिसर से न्यायरथ को विभिन्न तहसीलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए रवाना किया गया।

# सपा मुखिया ने पोछे मृतक बी.एल.ओ. गुलनाज़ के परिजनों के आंसू

मुरादाबाद।

सिविल लाइन स्थित जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दो लाख की सहायता राशि का चेक मृतक बी. एल. ओ. गुलनाज़ तबस्सुम की माँ और उनके ब'चों को जिलाध्यक्ष जयवीर सिँह यादव ने सौंपा और कहा कि समाजवादी पार्टी हर समय आपके साथ है. और आगे भी परिजनों की हर संभव सहायता व सहयोग किया जायेगा। बताते चलें की बीएलओ स्वर्गीय गुलनाज तबस्सुम आंगनबाड़ी

## मुहैया कराई दो लाख रूपये की सहायता

कार्यकत्री के पद कार्यरत थी। वह एसआईआर का काम कर रही थीं। कंपोजिट विद्यालय कन्या जूनियर हाई स्कूल मुग़लपुरा मुरादाबाद में भाग संख्या संख्या 78 पर एसआईआर का कार्य कर रहीं थीं कार्य के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके दो छोटे ब'चें हैं पुत्री सिदरा फातिमा ग्यारह वर्ष एवं पुत्र हमजा सात वर्ष हैं उससे पूर्व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतक बी. एल. ओ. सर्वेश कुमार जाटव को भी दो लाख की सहायता राशि का चेक दे चुकें हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जयवीर सिँह यादव,जुगल किशोर बाल्मीकि, सलाहउद्दीन मंसूरी,प्रेमबाबू बाल्मीकि, कमरुजमा सैफी, धर्मेंद्र यादव,महेंद्र सिँह मौजूद थे।

# मातृभाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान की आधारशिलाः प्रो. हरबंश दीक्षित

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हुई भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने अपना भाषण विविध भाषाओं - हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, बंगाली, भोजपुरी, ब्रज आदि में प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

लॉ के डीन प्रो. हरबंश दीक्षित अपने संक्षिप्त संबोधन में बोले, मातृभाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला है, जबकि प्राचार्य प्रो. एस्के सिंह ने कहा, बहुभाषिक शिक्षा एनईपी की भावना को परिलक्षित करती है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे इशू शुक्ला ने बंगाली भाषा में कहा कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, हमारी पहचान और संस्कृति की आत्मा है।

मातृभाषा का सम्मान करना अपने अस्तित्व को सम्मान देने के समान है। द्वितीय स्थान पर रहीं पायल मैत्री ने बंगाली भाषा में कहा कि मातृभाषा मेरे हृदय की पहली धुन है, इसी में मेरी आत्मा का नूर छुपा है। तृतीय स्थान पर रहे कुनाल बौद्ध ने कहा, भाषा मनुष्य की अंतरात्मा का दर्पण है; उसके शब्दों में उसके विचारों की गरिमा, भावनाओं की कोमलता और संस्कारों की गहराई झलकती है। प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. अमित वर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला और डॉ. कृष्णा मोहन मालवीय ने किया। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. नम्रता जैन ने किया।

# एनएसओ ने किया नौजवान हाफिज़ और पिता का सम्मान

मुरादाबाद।

नैशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन (एनएसओ) ने आज स्वागत रमज़ान की मुनासिबत से एक आज नौजवान हाफिज कुरआन मौ0 उमर व उसके पिता को सम्मानित किया। संगठन के हेड आफिस व्हाइट हाउस, गुजराती स्ट्रीट में एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता हाजी ज़ाहिद हुसैन ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में डॉ0 मो. सलमान अख्तर शामिल हुये जबकि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा अरशद बेग ने संचालन किया। इस अवसर पर उक्त नवयुवक हाफिज ने कुरआन व हदीस के हवाले से रमज़ान की एहमियत पर सम्बोधन किया, जिसकी संगठन के उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने प्रशंसा की तथा उसके उ'जवल भविष्य की कामना की। मीटिंग में उक्त के अलावा शफ़ात अहमद खाँ, मंसूर रेहमान, सैयद आजम अली, मो0 मौअज़्ज़म मौ. अनवर, मुफ्ती मौ. आजम, मुसर्रत हफीज़, डॉ0 शहाब उद्दीन, सोहराब अहमद खां, मास्टर राहत ज़मीं, हाजी मो. वसीम, सफदर नियाज़ी, इशरत हुसैन, फ़िरोज़ खाँ, हैदर अली व शारिक उस्मानी आदि मौजूद रहे।

# उद्यमियों की समस्याओं का खासख्याल रखें सभी विभागः कमिश्नर

मुरादाबाद।

यूपीसीडा, एसईजेड मुरादाबाद के प्रशासनिक भवन में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि उद्यमियो की समस्याओं का सभी विभाग विशेष ध्यान रखें। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं के अतिरिक्त एसईजेड एक्सपोर्टस एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा उठाये गये बिन्दु पाकबड़ा जंक्शन पर फ्लाई ओवर के पास लगने वाले जाम का हटाने, एसईजेड पहुँच मार्ग के लिये राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-24 से 02 दो विकल्पों को दिये जाने, एसईजेड जोन में जलापूर्ति हेतु वाटर कनेक्शन देने तथा पाकबडा से एसईजेड तक सिटी बस सर्विस का मुद्दा उठाया गया। आयुक्त आन्जनेय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक को पाकबड़ा जंक्शन पर फ्लाई ओवर के पास लगने वाले जाम की समस्या के समाधान हेतु निर्देश दिये। जलापूर्ति के सम्बन्ध में क्षेत्र प्रबन्धक गेसू मौर्या

द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र 04 इकाईयों द्वारा वाटर कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है। अतः केवल 04 इकाईयों हेतु जलापूर्ति देने पर पानी की लाईनों पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण पाईप लाईनों के फटने की प्रबल सम्भावना है। इस पर आयुक्त द्वारा जलापूर्ति के सम्बन्ध में निर्यातकों को अवगत कराया गया कि यदि प्रर्याप्त वाटर कनेक्शन हेतु इकाईयों द्वारा आवेदन किया जाता है तो यूपीसीडा द्वारा जलापूर्ति सुचारु करने की कार्यवाही की जायेगी। पाक़बडा से एसईजेड तक सिटी बस सर्विस के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24, पाकबडा से एसईजेड तक प्रति 15 मिनट के अन्दर प्राईवेट बसों का संचालन है जो पाकबडा से एसईजेड के गोलचक्कर पर रुकते हुये डींगरपुर-कुन्दरकी तक जाती है। इसके अतिरिक्त पाकबडा कनेक्टीविटी से एसईजेड तक ई-रिक्सा व ऑटो की सुविधा है। इसके अतिरिक्त एसईजेड एक्सपोर्टस एसोसिएशन तथा निर्यातकों को उपलब्ध सभी मूल भूत सुविधाओं से भी अवगत कराया गया। बैठक के उपरान्त आयुक्त द्वारा

## मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक में दिये निर्देश

एसईजेड प्रशासनिक भवन में वृक्षारोपण भी किया गया जिसके उपरान्त आयुक्त द्वारा औद्योगिक क्षेत्र एसईजेड मुरादाबाद के पॉकेट-ए एवं पॉकेट-बी के भ्रमण के दौरान पॉकेट-बी में मेसर्स दीवान इण्डिया की इकाई में उत्पादन कार्य भी देखा गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त गेसू मौर्या, क्षेत्र प्रबन्धक, एसईजेड, यूपीसीडा, श्री फिरोज, प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-चतुर्थ, यूपीसीडा, परवेज गिरि, प्रबन्धक (विद्युत) वद्युत खण्ड-द्वितीय, यूपीसीडा, आमिर इकबाल, सहायक विकास आयुक्त, एमएसईजेड, भूषण शर्मा, अधीक्षक, सीमा शुल्क एवं एसईजेड एक्सपोर्टस एसोसिएशन से विकास अरोडा, विकास अग्रवाल, अंकुर प्रकाश, एवं अन्य निर्यातक उपस्थित थे।

## छह साल के शीर्ष पर पहुंच सकता है सऊदी अरब से तेल का आयात, अमेरिकी दबाव से रूस से खरीद घटाने के असर

**नई दिल्ली ।** भारत इस महीने सऊदी अरब से छह साल से अधिक समय में सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है। रूस से कच्चे तेल की खरीदारी कम करने के लिए अमेरिका के भारत पर लगातार दबाव बनाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। केप्लर के प्रमुख अनुसंधान विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार, सऊदी अरब से तेल की आपूर्ति बढ़कर 10 लाख से 11 लाख बैरल प्रतिदिन होने की संभावना है। यह नवंबर, 2019 के बाद से उच्च स्तर होगा। यह रूस के अनुरूप है, जिससे दोनों आपूर्तिकर्ताओं के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो जाएगा। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बढ़ाने के कारण यह अंतर काफी बढ़ गया था। भारत पर अमेरिकी दबाव इस महीने की शुरुआत में तब ज्यादा हो गया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत एक व्यापार समझौते के तहत रूसी तेल की खरीदारी बंद करने पर सहमत हो गया है। हालांकि, भारत ने इस दावे पर सार्वजनिक रूप से कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। अगर तेल का प्रवाह 12 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचता है तो रूस इस महीने भी भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहेगा, लेकिन शिपमेंट में और भी गिरावट आने का अनुमान है। 2022 में यूक्रेन पर हुए आक्रमण के बाद भारत रूसी तेल का एक प्रमुख खरीदार बनकर उभरा, क्योंकि ओपेक और अन्य उत्पादक देश रूस को अपने तेल की कीमतों में भारी छूट देनी पड़ी। ऐसा इसलिए, क्योंकि अधिकांश अन्य खरीदार मॉस्को से जुड़ी ऊर्जा से दूर भाग रहे थे। भारत ने तब प्रतिदिन 20 लाख बैरल रूसी तेल आयात किया था।? केप्लर ने कहा, अगले महीने रूस से आयात में और कमी आ सकती है।?यह आयात प्रतिदिन 8 से 10 लाख बैरल के बीच रहेगा। यूरोपीय संघ के लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूसी कच्चे तेल पर पूरी तरह निर्भर नायरा एनर्जी की ओर से संचालित रिफाइनरी में अप्रैल एवं मई के दौरान रखरखाव कार्य के कारण होने वाले बंद से आयात की मात्रा में और भी कमी आने की आशंका है। रूस के लिए भारत में अपनी हिस्सेदारी खोना यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप से विस्थापित हुए उसके तेल के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार को कमजोर कर देता है। सऊदी अरब के लिए शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त करना सबसे तेजी से बढ़ते तेल बाजारों में से एक में रणनीतिक प्रभाव को बहाल करेगा।

## एआई आने से इंसानों की जगह नहीं लेगी मशीन, सिस्को के अधिकारी ने बताया कैसे बदलेंगे रोजगार के मौके

**नई दिल्ली ।** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच कॉरपोरेट जगत और आम लोगों में यह डर सता रहा है कि क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? सिस्को के प्रेसिडेंट और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर जीतू पटेल ने इन चिंताओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि एआई इंसानों को बेमानी नहीं बनाएगा, बल्कि यह मानवीय क्षमता और मूल्य को और बढ़ाएगा।

पटेल के अनुसार, असली कामयाबी तब मिलती है जब इंसानी समझ और निर्णय लेने की क्षमता को एआई के ऑटोमेशन के साथ मिलाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चैटबॉट से लेकर ऑटोनॉमस एजेंट तक, एआई सिस्टम तेजी से उन्नत हो रहे हैं, लेकिन इन्हें इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि उन्हें बदलने के लिए। पटेल ने अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने का उदाहरण देते हुए कहा कि कोई भी एआई किसी नर्स की जगह नहीं ले सकता। इंसानों में प्यार, समझ और देखभाल की बुनियादी जरूरत होती है, जिसे कोई मशीन पूरा नहीं कर सकती है। ऑटोमेशन के कारण नौकरियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पटेल ने माना कि काम का तरीका बदलेगा और कुछ पुरानी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हालांकि, उन्होंने आश्वस्त किया कि हर नौकरी का स्वरूप बदलेगा और एआई के कारण पूरी तरह से नए उद्योग और अवसर पैदा होंगे। मशीनें सहानुभूति, रचनात्मकता और समाज में योगदान देने की इंसानी फितरत की नकल नहीं कर सकती हैं।

कार्यस्थलों पर एआई डिजिटल सहकर्मियों के रूप में काम करेगा। इंसान अब उच्च-स्तरीय निर्णय लेने, रचनात्मकता और समस्याओं को सुलझाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। जीवन को केवल समुद्र तट को घूरने तक सीमित कर देना जीवन के उद्देश्य को ही चुनौती देगा, क्योंकि इंसानों में स्वभाव से ही कुछ नया बनाने और समाज में मूल्य जोड़ने की जन्मजात इच्छा होती है। वर्तमान में दुनिया एआई के दूसरे प्रमुख चरण में प्रवेश कर चुकी है, जबकि पहला चरण चैटबॉट्स का था जो बुद्धिमानी से सवालों के जवाब देते थे और यह किसी जादू जैसा लगता था। पटेल ने कहा कि इंसान किसी भी नई और जादुई लगने वाली तकनीक को बहुत जल्दी सामान्य मान लेते हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में वेमो की सेल्फ-ड्राइविंग कारों का उदाहरण देते हुए बताया कि पहली बार यह अनुभव हैरान करने वाला होता है। दूसरी बार बैठने पर इंसान डिस्ट्रैक्ट होकर ईमेल करने लगता है, और तीसरी बार तक कार की सीटों की शिकायत करने लगता है। तकनीकी प्रगति के कारण इंसानों के तालमेल बिठाने की यह तेज गति आगे भी जारी रहेगी। एआई से जुड़े खर्चों पर बात करते हुए पटेल ने कहा कि इसे ट्रेन करने और चलाने की लागत अभी अधिक है, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले दो वर्षों में इन्फरेंसिंग पर टोकन जनरेशन की लागत 1,000 गुना कम हो गई है। बुनियादी ढांचे पर कुल खर्च बढ़ेगा, लेकिन प्रति क्वेरी लागत समय के साथ तेजी से घटने की उम्मीद है। सिस्को के शीर्ष अधिकारी के अनुसार एआई के विकास का अर्थ समाज में इंसानी योगदान का अंत कतई नहीं है। भविष्य का कार्यस्थल ऐसा होगा जहां मशीनी पैमाने का उपयोग होगा, लेकिन उसके केंद्र में पूरी तरह से इंसान ही रहेंगे। तकनीक सस्ती होने के साथ-साथ यह कॉर्पोरेट्स के लिए विकास के नए द्वार खोलेगी और कार्यबल में इंसानों के महत्व को मजबूती से बरकरार रखेगी।

## ग्लोबल टैरिफ के बाद भारत पर 18 फीसदी नहीं, 10फीसदी शुल्क, ट्रंप ने कहा- व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं

**वॉशिंगटन ।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का एलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए जब ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर ग्लोबल टैरिफ के असर को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा। ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और फिलहाल यह 150 दिनों तक लागू रहेगा। उसके बाद अमेरिकी संसद में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद और उसके बाद ट्रंप द्वारा 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा? सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। कई देशों पर 10 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ था, जिनमें यूरोपीय संघ पर 15 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत, ब्रिटेन पर 10 प्रतिशत और भारत पर 18 प्रतिशत। अब ग्लोबल टैरिफ के बाद इन सभी देशों पर टैरिफ घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह भारत पर भी अब 18 के बजाय 10 प्रतिशत टैरिफ ही लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ घोषित अंतरिम व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा। भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। उनके अनुसार यह पहले की स्थिति से उलट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बताया। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ हटाए थे और नए ढांचे के तहत इसे घटाकर 18 प्रतिशत करने की बात कही थी। प्रेस वार्ता में ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को 200 प्रतिशत टैरिफ की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुरोध पर भारत ने रूस से तेल खरीद में कमी की। हालांकि इन दावों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। नए कार्यकारी के आदेश के तहत अमेरिका में आने वाले सभी आयातित सामान पर 10 प्रतिशत नया शुल्क लगेगा। यह 150 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय भुगतान असंतुलन को ठीक करने और अमेरिकी उद्योग, किसानों व निर्माताओं के हित में उठाया गया है। ट्रंप ने दोहराया कि टैरिफ उनकी आर्थिक नीति का अहम हिस्सा हैं और इससे अमेरिका को लाभ होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से अधिक जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय निराशाजनक है। उन्होंने कुछ जजों की आलोचना भी की। फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत नया अस्थायी आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी कर दिया।

## ब्रोकरेज ने इस शेयर को दी Sell रेटिंग, कहा- आ सकती है बड़ी गिरावट

**बिजनेस डेस्क ।** टाटा समूह की टेक्नोलॉजी कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने इस शेयर पर 'सेल' रेटिंग जारी की है और निवेशकों को मुनाफावसूली की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर के लिए 4,400 रुपए का लक्ष्य मूल्य तय किया है, जो मौजूदा स्तर से गिरावट का संकेत देता है। शुक्रवार को बीएसई पर टाटा एलेक्सी का शेयर 4,839.90 रुपए पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान शेयर 4,790 रुपए के निचले स्तर और 4,908 रुपए के उच्च स्तर के बीच रहा। कंपनी का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 6,733.50 रुपए है, जबकि निचला स्तर 4,601.05 रुपए दर्ज किया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से भी नीचे जा सकता है। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 43.90 प्रतिशत है, जबकि 56.10 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक शेयरधारकों के पास है। प्रमोटर समूह में सबसे बड़ी हिस्सेदारी Tata Sons की है, जिसके पास 42.21 प्रतिशत शेयर हैं। इसके अलावा Tata Investment Corporation के पास 1.69 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरधारकों में (एलआईसी) की 6.59 प्रतिशत और General Insurance Corporation of India की 1.18 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसी बीच टाटा एलेक्सी के प्रमोटर Tata Sons की अगले सप्ताह असाधारण आम बैठक (ईजीएम) प्रस्तावित है। इसमें Natarajan Chandrasekaran को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त करने पर मुहर लग सकती है। चंद्रशेखरन जनवरी 2017 से टाटा संस के चेयरमैन हैं और इससे पहले वे Tata Consultancy Services (टीसीएस) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रबंधन से जुड़े घटनाक्रम और ब्रोकरेज की रेटिंग आने वाले दिनों में शेयर की दिशा तय कर सकते हैं।

## वैश्विक तनाव के बीच खुदरा निवेशकों का भरोसा बरकरार, 15 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा निवेश

**नई दिल्ली ।** भारतीय शेयर बाजार में व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों की भागीदारी और निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। उतार-चढ़ाव के बावजूद जनवरी, 2026 में इन निवेशकों ने सेकंडरी मार्केट में रिकॉर्ड 16,944 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। यह अक्तूबर, 2024 के बाद से खुदरा निवेशकों की ओर से किया गया 15 माह में सर्वाधिक मासिक निवेश है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुद्ध निवेश का यह आंकड़ा बताता है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और कई देशों में तनाव के बीच सेकंडरी मार्केट में व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों की भागीदारी मजबूती से बढ़ रही है। इससे उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय बाजार को समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि खुदरा निवेशकों की खरीदारी में मासिक आधार पर भी बड़ी तेजी दर्ज की गई है। इस खरीदारी ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक सेकंडरी मार्केट में हुई निकासी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। नतीजतन, चालू वित्त वर्ष के दौरान सेकंडरी मार्केट से शुद्ध निकासी घटकर सिर्फ 687 करोड़ रुपये रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर प्राइमरी मार्केट के आंकड़ों को भी शामिल करें, तो व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों का चालू वित्त वर्ष में अब तक शुद्ध निवेश 40,685 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसमें आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें खुदरा निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।?आंकड़े यह भी बताते हैं कि सेकंडरी मार्केट की गतिविधियों में उतार-चढ़ाव के बावजूद खुदरा निवेशकों का इक्विटी बाजार के प्रति आकर्षण बना हुआ है। गतिविधियों में बीच-बीच बढ़ोतरी के बावजूद प्राइमरी मार्केट एलोकेशन समेत कुल खुदरा निवेश बीते वित्त वर्ष 2024-25 के 1.59 लाख करोड़ से काफी कम रहा है। इस रुझान से पता चलता है कि व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों ने बाजार में अपेक्षाकृत स्थिरता के समय ही पैसा लगाना जारी रखा है। साथ ही, पिछले साल की तुलना में भागीदारी बढ़ाने में ज्यादा सावधानी बरती है। घरेलू शेयर बाजार एक दिन पहले की बड़ी गिरावट से उबरते हुए शुक्रवार को बढ़त में बंद हुए।?बैंकिंग एवं धातु शेयरों में खरीदारी, व्यापार समझौते में प्रगति को लेकर आशावाद के साथ पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी की खबरों से बाजार को समर्थन मिला। सेंसेक्स 316.57 अंक उछलकर 82,814.71 पर बंद हुआ। दिन में यह 633.94 अंक तक उछल गया था। निफ्टी 116.90 अंक चढ़कर 25,571.25 पर बंद हुआ। सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 1.89 लाख करोड़ बढ़ गई। सेंसेक्स के 30 में 22 शेयर बढ़त में रहे। एनटीपीसी सर्वाधिक 2.73 फीसदी लाभ में बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुद्ध रूप से 934.61 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की।

# अब होगी असली परीक्षा: अभिषेक की खराब फॉर्म से बढ़ी चिंता, तिलक का स्ट्राइक रेट कर रहा परेशान

**अहमदाबाद ।** टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण में भारतीय टीम भले ही अजेय रही और उसने सभी चार मैच जीते, लेकिन अब तक उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। बल्लेबाजी हो या फील्डिंग दोनों ही मोर्चों पर टीम संघर्ष करती दिखी है। वहीं, गेंदबाजी अपेक्षाकृत संतोषजनक रही है, लेकिन अब गत चैंपियन टीम की असली परीक्षा शुरू होगी। शनिवार से सुपर आठ चरण की शुरुआत हो रही है और भारत अगले दौर में अपना पहला मैच रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने उतरेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन के नहीं चलने पर टीम प्रबंधन ने टी20 विश्व कप के लिए उनकी जगह ईशान किशन को अभिषेक शर्मा के जोड़ीदार के रूप में शामिल कर लिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों की ओपनिंग जोड़ी धीमे विकेटों पर स्पिनरों के खिलाफ गच्चा भी खा सकती है। भारत के शीर्ष क्रम को धीमे विकेटों पर स्पिनरों के सामने संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय टीम को दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों की ओपनिंग जोड़ी की कमी खल रही है। बाएं हाथ के ओपनरों की जोड़ी के खिलाफ अंगुली के स्पिनर असरदार रहे हैं। समस्या सिर्फ बाएं हाथ के ओपनरों की नहीं है।

नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आ रहे तिलक वर्मा भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अब तक विश्व कप में अभिषेक के साथ तिलक का भी प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। अभिषेक ने जहां इस विश्वकप में अपना खाता भी नहीं खोला है। वहीं, तिलक ने चार मैचों में 120.45 स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाए हैं। नंबर तीन पर यह स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, जबकि उनका करियर स्ट्राइक रेट 141.8 का है। तिलक ने अब तक कोई अर्धशतक भी नहीं लगाया है। उन्हें शुरुआत अच्छी मिली है, लेकिन एक बार भी वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। भारत को सुपर आठ में दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की चुनौती मिलेगी। अगर इनके खिलाफ बेहतर करना है तो

अभिषेक और तिलक को कुछ बड़ा करना होगा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रनों का अंबार लगाया। समान उछाल और एक गति से आ रही गेंदों पर भारत ने 5 मैचों में 238, 209, 155 (10 ओवर में), 165 और 271 रन जैसे बड़े स्कोर बनाए। इस सीरीज में बल्लेबाजों के प्रदर्शन ने विश्व कप में धूम-धड़ाके की उम्मीदें जगाईं, लेकिन विश्व कप के पहले मैच से ही सह मेजबान भारत को अपने घर में मनमाफिक पिचें नहीं मिलीं।

ये पिचें धीमी थीं जिन पर अभिषेक और तिलक वर्मा जैसे स्ट्रोक प्लेयर को दिक्कत आई। अभिषेक तेजी से बल्ला घुमाते हैं और पिच पर रुककर आ रही गेंद पर वह अपने बल्ले की स्विंग से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। भारत ने अब तक इस विश्व कप में एक बार ही नामीबिया के खिलाफ 200 से अधिक का स्कोर किया है। सुपर आठ में भी अगर धीमी पिचें मिलीं तो यहां भारतीय बल्लेबाजों को उसी तरह से तालमेल बिठाना होगा जैसा ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की पारी और सूर्यकुमार ने अमेरिका के खिलाफ 84 रन की पारी के दौरान दिखाया था। शुक्रवार को अभ्यास के दौरान निगाहें अभिषेक पर रहीं। अभिषेक ने कोच गौतम गंभीर से लंबी मंत्रणा की। गंभीर उन्हें कई गुर देते नजर आए। बाद में उन्होंने कैच का अभ्यास किया और स्पिन गेंदबाजी भी की।

गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि अभिषेक को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम विश्व कप के अहम दौर से गुजर रहे हैं। हमें उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वह गेंद को अच्छी तरह हिट कर रहे हैं। उन्हें अच्छी शुरुआत की जरूरत है। उन्होंने धीमी पिचों पर कहा कि क्यूरेटर सर्वश्रेष्ठ पिचें देने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्रुप दौर में भारतीय टीम के लिए सकारात्मक पक्ष यह है कि उसकी गेंदबाजी शानदार रही है और चारों मैच में किसी एक खिलाड़ी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। अमेरिका के खिलाफ सूर्यकुमार चले, नामीबिया के खिलाफ ईशान और हार्दिक ने जिम्मेदारी संभाली, पाकिस्तान के खिलाफ ईशान ने यादगार पारी खेली और नीदरलैंड के खिलाफ शिवम दुबे ने नहीं भुलाने वाली पारी खेली। यह प्रारूप ऐसा है जिसमें एक खिलाड़ी ने मोर्चा संभाल लिया तब भी काम बन जाता है, लेकिन सूर्यकुमार और गंभीर हमेशा सभी की भूमिका की वकालत करते रहे हैं। सुपर आठ का मंच भी ऐसा है जहां एक नहीं हर खिलाड़ियों को मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी। अकेले मोर्चा संभालने में हमेशा जोखिम ज्यादा रहता है और भारत को चारों मैचों में खेल के किसी न किसी एक पक्ष में संघर्ष जरूर करना पड़ा। भारत अब किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू हुई है। सूर्यकुमार की अगुआई वाली टीम को अगर खिताब बरकरार रखना है तो ग्रुप चरण में की गई गलतियों से सीख लेना होगा।

## सुपर आठ का रोमांच आज से, पाकिस्तानी स्पिन और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कौशल की होगी परीक्षा

**कोलंबो** टी20 विश्वकप में सुपर आठ चरण का रोमांच शनिवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले मुकाबले से शुरू होगा। दोनों टीमें लीग चरण में 2024 की विजेता और उपविजेता से हार चुकी हैं। पाकिस्तान को गत चैंपियन भारत से 61 रन, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण अफ्रीका से सात विकेट से करारी शिकस्त मिली थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच असल टक्कर स्पिन और बल्लेबाजी कौशल की होगी। पाकिस्तान के पास उस्मान तारिक की अगुआई में बेहतर स्पिन गेंदबाजी आक्रमण है, तो न्यूजीलैंड को टिम सीफर्ट और फिन एलन की सलामी जोड़ी के अलावा, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र और मार्क चेपमैन मजबूती प्रदान करते हैं। सलमान आगा की पाकिस्तान के लिए मजबूत पक्ष यह है कि उसकी टीम कोलंबो और श्रीलंकाई परिस्थितियों से टी20 विश्वकप शुरू होने से पहले ही परिचित हो सुकी है। आर. प्रेमादासा स्टेडियम में वह दो मुकाबले खेल चुकी है। न्यूजीलैंड के लिए दिक्कत यह है कि उसके खिलाड़ी जनवरी से ही भारत में बल्लेबाजी के अनुकूल पिचों पर खेलते आ रहे हैं। सुपर आठ के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कोलंबो की धीमी पिच पर पाकिस्तानी स्पिनरों से निपटने के लिए खास रणनीति बनानी होगी। हालांकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारत के विश्वस्तरीय स्पिनरों का अच्छे से सामना कर चुके हैं। टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने अब तक सात मैच खेले हैं। पाकिस्तान ने पांच और न्यूजीलैंड ने दो मैच जीते हैं। अतीत को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड की टीम सतर्कता के साथ ही आक्रामक रुख अपनाना चाहेगी। न्यूजीलैंड को पता है कि पाकिस्तान के पास स्पिन आक्रमण है, लेकिन उसकी बल्लेबाजी में गहराई कम नहीं है। वहीं, तेज गेंदबाज खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी साहिबजादा फरहान के आसपास ही घूमती है। तेज गेंदबाजी असर नहीं दिखा पा रही है। मिचले सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी पाकिस्तान पर बढ़त दिलाती है।

## भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच में दिखेगा दो भाइयों का रणनीतिक मुकाबला, आमने-सामने होंगे मोर्कल बंधु

**अहमदाबाद ।** भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को अहमदाबाद में टी20 विश्व कप का सुपर आठ मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर भाइयों की जोड़ी को एक ही जर्सी में पसीना बहाते देखा गया है, चाहे वो स्टीव और मार्क वॉ हों या भारत के पठान और पांड्या ब्रदर्स। लेकिन रविवार को एक ऐसा मंजर दिखेगा जो क्रिकेट इतिहास में विरला ही होता है। वर्षों तक साथ खेलने वाले दो सगे भाई अलग-अलग डगआउट में बैठकर प्रतिद्वंद्वी टीमों के लिए रणनीति बनाते नजर आएंगे और घर पर बैठी उनकी मां इस उलझन में होंगी कि आखिर समर्थन किसे करें। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एल्बी मोर्कल और मोर्ने मोर्कल की भाइयों की जोड़ी इस समय ऐसी ही स्थिति में है। एल्बी इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के विशेष सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि मोर्ने भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले कोचिंग दल में गेंदबाजी कोच की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये दोनों अब एक-दूसरे के खिलाफ माइंड गेम खेलते नजर आएंगे। एल्बी ने हाल ही

में मजाकिया अंदाज में कहा था, 'नहीं, हम अभी एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे। हमसे ज्यादा हमारी मां परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत का समर्थन करें या दक्षिण अफ्रीका का।' ग्रुप चरण में दोनों टीमों ने अपराजित रहते हुए सुपर-आठ में जगह बनाई है। यह सुपर आठ चरण में दोनों टीमों का यह पहला मैच होगा। मोर्ने ने भी स्वीकार किया कि बड़े भाई से उनकी बातचीत ज्यादा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें मैदान पर आते देखा, लेकिन ज्यादा बात नहीं हुई। फिर भी उन्हें देखकर अच्छा लगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे कई प्रेरक उदाहरण रहे हैं जब भाइयों ने साथ खेलकर इतिहास रचा। इस सूची में चैपल बंधु (इयान और ग्रेग), वॉ बंधु (स्टीव और मार्क), अमरनाथ बंधु (मोहिंदर, सुरिंदर और राजिंदर), पठान बंधु (इरफान और यूसुफ), पांड्या बंधु (हार्दिक और कृणाल), मोहम्मद बंधु (हनीफ, सादिक, मुश्ताक, वजीर) और हेडली बंधु (रिचर्ड और डेल) के नाम शामिल हैं। इसमें कुछ अपवाद भी रहे हैं जब भाइयों ने अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व किया हो। इसमें सैम कुरेन का इंग्लैंड के लिए खेलना और उनके भाई बेन कुरेन का जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। मोर्कल बंधुओं का मामला थोड़ा अलग है। यहां मुकाबला मैदान पर खिलाड़ियों के बीच नहीं, बल्कि रणनीति और दिमाग की जंग का है। क्रिकेट में सगे भाइयों के बीच इस तरह की दिमागी जंग के उदाहरण कम ही देखने को मिले हैं। करियर के लिहाज से मोर्ने का अंतरराष्ट्रीय सफर अधिक लंबा और प्रभावशाली रहा। उन्होंने 86 टेस्ट में 309 विकेट लिए। वहीं एल्बी सीमित ओवरों के विशेषज्ञ रहे और टी20 व वनडे मिलाकर 100 से अधिक मैच खेले। एल्बी के करियर का एक कम चर्चित पहलू यह भी है कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के शुरुआती वर्षों में वह कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भरोसेमंद खिलाड़ी रहे।

## दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले बढ़ी भारत की चिंता, हार्दिक के शॉट पर घायल हुआ ये तेज गेंदबाज

अहमदाबाद भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर आठ मुकाबले के लिए अहमदाबाद में है। दोनों टीमों के बीच ये मैच 2024 विश्व कप के फाइनल की याद दिलाएगा। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल के लिए कदम आगे बढ़ाएगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले भारत की चिंता बढ़ गई है। विश्व कप से पहले ही टीम खिलाड़ियों की चोट की समस्या से जूझ रही थी। जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा तबीयत खराब होने की वजह से एक मैच में नहीं खेल सके थे, जबकि हर्षित राणा को तो चोट के कारण टूर्नामेंट से ही बाहर होना पड़ा था। हर्षित की जगह मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका मिला था। सिराज अमेरिका के खिलाफ भारत के पहले मैच में खेलने उतरे थे और उन्होंने तीन विकेट भी लिए थे। अब भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना है तो इससे पहले ही टीम के तेज गेंदबाज सिराज चोटिल हो गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभ्यास के दौरान हार्दिक पांड्या के शॉट पर सिराज चोटिल हुए। गेंद सिराज के बाएं पैर के घुटने में लगी। सिराज इस दौरान दर्द में दिखे और लंगड़ाते हुए नेट्स से बाहर आए। भारतीय टीम प्रबंधन ने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को ही ज्यादातर मैचों में मौका दिया है। शुक्रवार को अभ्यास के दौरान निगाहें अभिषेक पर रहीं। अभिषेक ने कोच गौतम गंभीर से लंबी मंत्रणा की। गंभीर उन्हें कई गुर देते नजर आए।

## विवादों में पाकिस्तान क्रिकेट: पीसीबी का बढ़ा सिरदर्द, पीएसएल फ्रेंचाइजी में स्वामित्व की जंग

**नई दिल्ली ।** पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर प्रशासनिक अराजकता और अंदरूनी खींचतान की वजह से सुर्खियों में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) इन दिनों अपनी ही टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में मची स्वामित्व की जंग से जूझ रहा है। हालत यह है कि मैदान से ज्यादा चर्चा अब कोर्ट और बंद कमरों में हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया, हाल ही में नीलामी में खरीदी गई सियालकोट फ्रेंचाइजी में बहुमत हिस्सेदारी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सियालकोट की इस टीम को 185 करोड़ रुपये में एक कंसोर्टियम ने खरीदा था, जिसमें कामिल खान भी शामिल हैं। मामला तब गरमाया जब एक प्रमुख हिस्सेदार मुहम्मद शाहिद ने पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर को शिकायत भेजी। शाहिद का दावा है कि उनके पास फ्रेंचाइजी के 76% शेयर हैं, जबकि बाकी 24% हिस्सेदारी रखने वाले पार्टनर उनकी जानकारी और सहमति के बिना शेयर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश में रहने वाले शाहिद ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक शेयरधारक अपने हिस्से से ज्यादा शेयर डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लीग में स्वामित्व संरचना इतनी अस्पष्ट कैसे हो सकती है? विवाद सिर्फ नई फ्रेंचाइजी तक सीमित नहीं है। पीएसएल की जानी-मानी टीम लाहौर कलंदर्स में भी मालिकाना हक को लेकर परिवार के भीतर टकराव सामने आया है। फ्रेंचाइजी के मूल मालिकों में से एक फवाद राणा ने अदालत से अपने पक्ष में फैसला मिलने के बाद फिर से पीएसएल प्रबंधन को शिकायत दी है। अदालत में दायर याचिका में उन्होंने अपने भाइयों आतिफ राणा और समीर राणा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी कंपनी के शेयर उनकी जानकारी के बिना बेच दिए। कोर्ट ने फवाद राणा के पक्ष में फैसला सुनाया। लगातार सामने आ रहे इन विवादों ने पीसीबी की प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

# 'व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं', ट्रंप का बयान; ग्लोबल टैरिफ के बाद भारत पर कितना लगेगा शुल्क?

**वॉशिंगटन ।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद और उसके बाद ट्रंप द्वारा 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा? सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का एलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए जब ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर ग्लोबल टैरिफ के असर को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा।

ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और फिलहाल यह 150 दिनों तक लागू रहेगा। उसके बाद अमेरिकी संसद में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद और उसके बाद ट्रंप द्वारा 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा? सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा।

कई देशों पर 10 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ था, जिनमें यूरोपीय संघ पर 15 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत, ब्रिटेन पर 10 प्रतिशत और भारत पर 18 प्रतिशत। अब ग्लोबल टैरिफ के बाद इन सभी देशों पर टैरिफ घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह भारत पर भी अब 18 के बजाय 10 प्रतिशत टैरिफ ही लागू होना चाहिए। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ घोषित अंतरिम व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा। भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। उनके अनुसार यह पहले की स्थिति से उलट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बताया। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ हटाए थे और नए ढांचे के तहत इसे घटाकर 18 प्रतिशत करने की बात कही थी। प्रेस वार्ता में ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को 200 प्रतिशत टैरिफ की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुरोध पर भारत ने रूस से तेल खरीद में कमी की। हालांकि इन दावों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। नए कार्यकारी के आदेश के तहत अमेरिका में आने वाले सभी आयातित सामान पर 10 प्रतिशत नया शुल्क लगेगा। यह 150 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय भुगतान असंतुलन को ठीक करने और अमेरिकी उद्योग, किसानों व निर्माताओं के हित में उठाया गया है। ट्रंप ने दोहराया कि टैरिफ उनकी आर्थिक नीति का अहम हिस्सा हैं और इससे अमेरिका को लाभ होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से अधिक जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय निराशाजनक है। उन्होंने कुछ जजों की आलोचना भी की। फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत नया अस्थायी आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी कर दिया।

# दिल्ली के श्रेयस मिश्रा ने रचा इतिहास, JEE MAIN 2026 में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त

दिल्ली के प्रतिभाशाली छात्र श्रेयस मिश्रा ने JEE MAIN 2026 की परीक्षा में देशभर में प्रथम स्थान हासिल कर राजधानी सहित पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरी दिल्ली को गर्व से भर दिया है। श्रेयस मिश्रा की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम है। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक JEE MAIN में शीर्ष स्थान प्राप्त करना अत्यंत गौरव की बात मानी जाती है। पूर्व भाजपा विधायक एवं गांधीनगर विधानसभा, दिल्ली के वरिष्ठ नेता अनिल बाजपेई ने श्रेयस मिश्रा को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि श्रेयस की सफलता से पूरी दिल्ली गौरवान्वित हुई है और यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने श्रेयस मिश्रा के उज्ज्वल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे मेधावी छात्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।